प्रभात खबर

रांची, शुक्रवार
11.11.2016

गौरव का क्षण. जस्टिस डीएन पटेल ने दी जानकारी

पूर्वी जोन से लगातार दूसरी बार रांची डीएलएसए सर्वश्रेष्ठ

जानकारी देते जस्टिस पटेल.

वरीय संवाददाता ▸ रांची

भारत के पूर्वी जोन से लगातार दूसरी बार रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) सर्वश्रेष्ठ रहा. इस उपलब्धि के लिए नौ नवंबर को विधिक सेवा दिवस के अवसर पर नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने डीएलएसए को अवार्ड प्रदान किया. प्राधिकार की ओर से रांची के प्रधान न्यायायुक्त सह अध्यक्ष नवनीत कुमार ने मुख्य न्यायाधीश से प्रमाण पत्र व अवार्ड प्राप्त किया. उत्तर प्रदेश, बिहार, उतराखंड, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, अंडमान-निकोबार व झारखंड के जिलों में से रांची डीएलएसए के कार्यों को उत्कृष्ट व सबसे बेहतर माना गया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के अलावा नालसा ने भी इसकी प्रशंसा की है. इस उपलब्धि के लिए डीएलएसए के सभी टीम व उसके सदस्य बधाई के पात्र हैं.

उक्त बातें झारखंड हाइकोर्ट के वरीय न्यायाधीश व झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल ने कही. वे गुरुवार की रात में झालसा के सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि देश में पहली बार झारखंड में बाल लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसकी प्रशंसा राष्ट्र स्तर पर की जा रही है. इससे पहले डीएलएसए रांची के अध्यक्ष सह प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने जस्टिस पटेल को अवार्ड व प्रमाण पत्र भेंट की. उन्होंने प्राधिकार द्वारा किये जा रहे कार्यों की विस्तार जानकारी दी. इस अवसर पर हाइकोर्ट लीगल सर्विसेज अथोरिटी के सचिव संतोष कुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

एक साथ 500 स्कूलों में होगा लीगल लिटरेसी क्लब का उदघाटन

कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस पटेल ने कहा कि राज्य में एक साथ एक ही दिन 500 स्कूलों में लीगल लिटरेसी क्लब का उदघाटन किया जायेगा. इसमें सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, मॉडल विद्यालय व एकलव्य विद्यालय शामिल हैं. यह लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स में भी दर्ज होगा. लिम्का की ओर से झालसा को प्रस्ताव मिला है. जस्टिस पटेल ने कहा कि एक लाख वार्षिक आयवाले लोग लीगल एड क्लिनिक से लाभ उठा सकते हैं. उन्हें अधिवक्ता की सेवा, कोर्ट फीस आदि की सुविधा मिलेगी. जिन्होंने कोर्ट फीस जमा कर दी है, उन्हें वापस मिल जायेगा. छोटे-छोटे मामलों को कोर्ट में ले जाने के बदले लीगल एड क्लिनिक में ले जाना चाहिए.

10 दिसंबर को लोक अदालत में विवि के मामले होंगे निष्पादित

जस्टिस पटेल ने कहा कि 10 दिसंबर को लोक अदालत लगायी जायेगी. इसमें विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मचारियों की वर्षों पुरानी लंबित सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया जायेगा. लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान संभव होगा. सरकार को 19 नवंबर तक संबंधित विश्वविद्यालयों को राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया है. तीन दिसंबर तक चेक भी तैयार हो जायेंगे. लोक अदालत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा, चांसलर सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे. जस्टिस पटेल ने यह भी कहा कि विवि से संबंधित अन्य लंबित मामले यदि छूट गये हैं, तो उन्हें भी लोक अदालत में लाया जा सकता है.

प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने विज्ञान भवन में प्रमाण पत्र व शील्ड देकर किया सम्मानित

रांची ने दूसरी बार जिला विधिक सेवा प्राधिकार का खिताब हासिल किया

- वर्ष 2015 में भी सर्वश्रेष्ठ का मिला था प्रमाणपत्र
- पूर्वी जोन के आठ राज्यों के जिलों में रांची जिला सबसे अव्वल रहा

संवाददाता

रांची। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची ने लगातार दूसरी बार पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला विधिक सेवा प्राधिकार का प्रमाणपत्र हासिल किया है। बुधवार नौ नंवबर को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में विधिक सेवा दिवस पर आयोजित समारोह में देश के प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने रांची को सर्वश्रेष्ठ जिला विधिक सेवा प्राधिकार (पूर्वी जोन) चुने जाने पर शील्ड एवं प्रमाणपत्र प्रदान किया। यह प्रमाणपत्र डालसा के अध्यक्ष सह रांची के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार को दिया गया। इस अवसर पर झालसा के सदस्य सचिव एके राय, हाइकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के सचिव संतोष कुमार व डालसा सचिव राजेश कुमार सिंह भी उपस्थित थे। प्रमाणपत्र व शील्ड मिलने पर झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल ने सभी पदाधिकारियों एवं मेडिएटरों की प्रशंसा के साथ-साथ सराहना की। प्रमाणपत्र लेने के बाद वापस रांची पहुंचने पर गुरुवार को जस्टिस डीएन पटेल ने टीम का स्वागत किया। जस्टिस श्री पटेल ने डोरंडा स्थित न्याय सदन में मीडियाकर्मियों को बतलाया कि झारखंड वैकल्पिक न्याय व्यवस्था में आगे बढ़ रहा है। इसमें रांची जिला का बेहतर प्रदर्शन किया है। किसी भी क्षेत्र में लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठता का शील्ड लेना सहज नहीं है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने काफी मेहनत की है। बेहतर रिजल्ट दिया है और लगातार दे रहा है। बताते चले कि प्रत्येक वर्ष नौ नंवबर को विधिक सेवा दिवास के रूप में मनाया जाता है। इसमें देश भर के राज्य विधिक सेवा प्राधिकारों के सदस्य सचिवों की उपस्थिति में सर्वश्रेष्ठ पारा लीगल वॉलेन्टियर व सर्वश्रेष्ठ जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सम्मानित किया जाता है।

आठ राज्यों के जिलों में सर्वश्रेष्ठ जिला रहा रांची

जस्टिस डीएन पटेल ने बताया कि पूर्वी जोन में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य आता है। इस राज्यों के जिलों से रांची जिला ने बाजी मारी। वर्ष 2015 में भी यह उपलब्धि हासिल की थी।

इन वजहों से रांची आया सर्वश्रेष्ठ

पीड़ितों को मुआवजा दिलाने में रांची डालसा आगे रहा। इसने कॉम्प्ट फंड मे डायन कहकर पीड़ित किये गये महिलाओं को 25 हजार रुपए प्रति पीड़ित मुआवजा दिया। जेल में संसीमित दोषसिद्ध के आये को 1/3 भाग पीड़ितों को युद्धस्तर पर दिलाया। पॉस्को के पीड़ितों को मुआवजा दिलाया। नालसा के सात योजनाओं को धरातल पर लागू किया। जुवेनाइल एक्ट के तहत इटकी में बालाश्रय खुला तथा डुमरदगा संप्रेक्षण गृह को आदर्श बनाया गया। देश में आयोजित प्रथम बाल लोक अदालत में रांची में सर्वाधिक मामलों को निष्पादन किया। मध्यस्थता से मामलों का निष्पादन 72 फीसदी रहा। लोक अदालत के द्वारा अदालत में लंबित मामले के निष्पादन में आगे रहा।

सभी जिलों में एक साथ 500 स्कूलों में कानूनी साक्षरता क्लब खुलेगा

जस्टिस डीएन पटेल ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में एक साथ 500 स्कूलों में लीगल लिटरेसी क्लब खोला जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा यह अपने आप में एतिहासिक होगा। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाएगा। कानूनी साक्षरता क्लब राज्य के अनुसूची जनजाति के बच्चे व बच्चियों को कानूनी रूप से साक्षर बनाया जाएगा। अगले महीने दस दिसंबर को मेगा लोक अदालत में विश्वविद्यालय से जुड़े मामलों को निष्पादन किया जाएगा। जिसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जाएगा। मामलों को सूचीबद्ध किया जा रहा है।